भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 5009
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी उद्योग को बढ़ावा

5009. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और उसमें वृद्धि करने, विशेषकर दुग्ध उत्पादन और डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने ओडिशा में विशेषकर अवसंरचना विकास, पशुधन प्रबंधन और मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद के संदर्भ में डेयरी किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट योजनाएं या वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूध की गुणवत्ता, उत्पादकता और आय में सुधार लाने के लिए ओडिशा में डेयरी किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने की योजना है कि ओडिशा में डेयरी क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बने?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) दूध उत्पादन, तथा डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार करने और डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए, भारत सरकार ओडिशा सहित पूरे देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और अन्य योजनाओं को लागू कर रही है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन और अन्य पहलों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पिछले दशक में देश में दूध उत्पादन में 63.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 239.3 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह, ओडिशा में दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 18.98 लाख टन से 39% बढ़कर वर्ष 2023-24 में 26.30 लाख टन हो गया है।

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: इस योजना का उद्देश्य देशी नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी का आनुवंशिक उन्नयन, दूध उत्पादन और बोवाईन उत्पादकता में वृद्धि करना है, और इस प्रकार किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

   i. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना और उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के सीमन का उपयोग करके किसानों के द्वार पर निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ प्रदान करना है। ओडिशा में, अब तक 46.53 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 61.10 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और इस कार्यक्रम के तहत 29.48 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

   सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। डेयरी व्यवसाय में लगे छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% तक प्रोत्साहन उपलब्ध है। हाल ही में देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक शुरू की गई है और इस तकनीक से सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत 800 रुपये से घटकर 250 रुपये प्रति खुराक रह जाएगी। ओडिशा में, इस परियोजना के तहत अब तक 1,24,690 खुराकें खरीदी गई हैं और भारत पशुधन के अनुसार 38,398 किसान लाभान्वित हुए हैं।

ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है और अब तक ओडिशा राज्य में 1500 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है।

ii आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: भारत में पहली बार देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए बोवाईन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था 21,000 रुपए की कुल लागत में से 5,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है।

देशी कल्चर मीडिया की शुरुआत: देश में आईवीएफ तकनीक को और बढ़ावा देने के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के लिए देशी मीडिया की शुरुआत की गई है। यह देशी कल्चर मीडिया महंगे आयातित मीडिया की तुलना में सस्ती दरों पर उपलब्ध है, जिससे आईवीएफ तकनीक उचित दरों पर उपलब्ध हो जाती है।

iii सीमन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण: सीमन उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाने के लिए कटक स्थित एक सीमन केन्द्र के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ओडिशा राज्य को निधियां जारी की गई है।

iv जागरूकता कार्यक्रम और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ा रैलियों और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए ओडिशा को निधियां जारी की गई हैं। अब तक, राज्य ने 1500 शिविर आयोजित किए हैं और पशु प्रबंधन, दूध की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए 75,000 किसानों को प्रशिक्षित किया है।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): यह योजना राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओडिशा को 1591.08 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

3. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): यह योजना खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने तथा डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ भी स्थापित की जाती हैं। यह योजना ओडिशा सहित देश में रोग मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में विभाग की एक पहल है, जिससे पशुधन उत्पादों के लिए बाजार के अवसर पैदा होते हैं।

4. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM): पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने एनडीडीबी के साथ मिलकर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एनडीएलएम के तहत "भारत पशुधन" नामक डेटाबेस विकसित किया है। यह डेटाबेस प्रत्येक पशुधन को आवंटित एक विशिष्ट 12-अंकीय टैग आईडी का उपयोग करके विकसित किया गया है। ओडिशा में कुल 1.65 करोड़ पशुओं को डेटाबेस पर पंजीकृत किया गया है। सभी हितधारक एक ओपन-सोर्स एपीआई आधारित आर्किटेक्चर के माध्यम से एक ही डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। एनडीएलएम पशुधन की ट्रेसबिलिटी बनाए रखने की दिशा में एक पहल है, जिससे मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

5. मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों का निर्यात संवर्धन और प्रमाणन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) को सौंपा गया है। विभाग ने संयुक्त कार्य समूह (JWG), तकनीकी कार्य समूह आदि जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से भारतीय डेयरी उत्पादों के निर्यात और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है।

******